

>

Title: Alleged custodial death of a dalit youth at Sakaldiha Police Station in Chandauli district of Uttar Pradesh.

**श्री रामकिशुन (चन्दौली):** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में एक दलित युवक को जनपद चन्दौली में पुलिस की हिरासत में पीट-पीट कर मार दिया गया। इतना ही नहीं, वहां पूरा पुलिस प्रशासन इस घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। वह पढ़ा-लिखा गरीब परिवार का नौजवान था। ...[\(व्यवधान\)](#)

अध्यक्ष महोदया, यह इतना गंभीर मसला है, उत्तर प्रदेश का डीजीपी कहता है कि उसे मारा नहीं गया था, बल्कि उसका हार्ट फेल हो गया था। मेडिकल रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट में डाक्टर कहता है कि उसका ब्रेन हेमरेज हुआ, जब कि लाठियों की चोट उसके गर्दन पर थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि वह पुलिस की कार्यवाही में नहीं मारा गया।...[\(व्यवधान\)](#)

अध्यक्ष महोदया, दो भाइयों में मामूली सी कहा-सुनी हुई थी। पुलिस का कोई हक नहीं बनता था कि उसे उसके घर से घसीट कर ले जाकर थाने में बंद कर दे। सत्ता पक्ष के एक नेता के इशारे पर उसके दूसरे भाई को पीट कर मारा गया।...[\(व्यवधान\)](#) इस घटना से पूरा चंदौली उबल रहा था। ये तमाम अखबारों की कटिंगें हैं, दैनिक जागरण ने लिखा है - "उबल पड़ा चंदौली।" वहां तमाम तरह की घटनाएं हुईं, तमाम दलितों को अपमानित किया गया। उस परिवार को आज तक वहां न्याय नहीं मिला।...[\(व्यवधान\)](#)

**अध्यक्ष महोदया :** आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं, वह बता दीजिए।

â€¦[\(व्यवधान\)](#)

**श्री रामकिशुन :** अध्यक्ष महोदया, मैं केन्द्र सरकार के माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि यह अनुसूचित जाति और दलित का मामला है। इसलिए इस पूरी घटना की जांच कराई जाए। उस दलित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। जिन पुलिस वालों ने उसे मारा, उनके खिलाफ धारा 302 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सस्पेंड किया जाए। तब उसकी जांच होगी। उसमें सत्ता पक्ष के एक नेता का हाथ है। वह पुलिस से मिला हुआ था। उसका बयान आ चुका है। उसकी मां अस्पताल में रो-रो कर चिल्ला रही है कि मेरे बेटे को पुलिस ने मार डाला। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि इस घटना की सी.बी.आई. द्वारा जांच कराई जाए और जितने लोग उसमें लिप्त हैं, जितने लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम कर के उन्हें जेल भेजा जाए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उस परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए।

मैंडम, आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि वहां दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। पूरा चन्दौली जिला नक्सल प्रभावित इलाका है। वहां जो गरीबों की हालत है, वह बयान नहीं की जा सकती है। ...[\(व्यवधान\)](#)

**अध्यक्ष महोदया :** अब आपकी बात पूरी हो गई है। कृपया बैठ जाएं। श्री भर्तृहरि महताब।

â€¦[\(व्यवधान\)](#)

**श्री रामकिशुन :** मैंडम, वह नक्सल प्रभावित जिला है। इसलिए जरूरी है कि ...[\(व्यवधान\)](#)

**अध्यक्ष महोदया :** ठीक है। आपकी बात पूरी हो गई है। कृपया अब आप बैठ जाइए।

â€¦[\(व्यवधान\)](#)

**अध्यक्ष महोदया :**

श्री पन्ना लाल पुनिया, अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध कर रहे हैं।

...(Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri B. Mahtab is saying.

(Interruptions) â€¦[\\*](#)

**अध्यक्ष महोदया :** आप बैठ जाइए। उन्होंने अपनी बात कह दी है।

â€¦[\(व्यवधान\)](#)

**अध्यक्ष महोदया :** डॉ. रघुवंश प्रसाद जी, आप बैठ जाइए। उन्होंने अपनी बात कह दी है।

â€¦[\(व्यवधान\)](#)

**श्री मुलायम सिंह यादव :** महोदया, वहां तो एक मंत्री को गोली मार दी गई। ...[\(व्यवधान\)](#)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, मैं खड़ी हूँ। आप कृपया बैठ जाइए।

मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि दलितों पर जब भी अत्याचार हों, वह एक गम्भीर मामला हो जाता है। इसलिए उस पर हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। अगर आप नोटिस देंगे, तो सिर्फ इस मामले में ही नहीं, बल्कि हरिजनों की क्या स्थिति है और उनकी सुरक्षा के संबंध में जो भी प्रश्न हैं, उन पर विचार कर सकते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदया, सदन में मंत्री महोदय बैठे हैं। सरकार क्यों चुप बैठी हुई है ? इस पर मंत्री महोदय को कुछ बोलना चाहिए।  
...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, इस विषय में कुछ बोलना चाहते हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): As you have rightly observed, Madam, it is a very serious matter. The Government took note of it. At the appropriate time, the Government will come out with a statement on this issue.

---